स्वच्छता में निवेश का अर्थशास्त्र

–अरुण जेटली

स्वच्छता तक पहुंच बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्या नहीं है बल्कि इसमें अधिक गहरा व्यवहार संबंधी एवं सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ काम करता है। 60 करोड़ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ऐसी चुनौती है, जिसका बीड़ा संभवतः दुनिया में कभी किसी ने नहीं उठाया है। इसे सघन, समयबद्ध हस्तक्षेप से ही हासिल किया जा सकता है, जिसे सर्वोच्च–स्तर से चलाया जाए और जिसमें समाज के सभी वर्ग और सरकार शामिल हों।

कहते हैं, जिसका समय आ गया है उसे कोई रोक नहीं सकता! रक्तरंजित विश्वयुद्ध के बाद जब हिंसा का बोलबाला था, उस समय भारत ने अहिंसक सविनय अवज्ञा के जरिए, सत्याग्रह के जरिए आज़ादी हासिल की। पूरा देश महात्मा गांधी की आवाज के पीछे चल पड़ा और भारत ने दुनिया के सामने उदाहरण स्थापित करते हुए आज़ादी हासिल की। वह एक विचार था, जिसका समय आ चुका था। इसी तरह जब देश सबसे ज्यादा खुले में शौच करने वाले देशों की कुख्यात सूची में बहुत ऊपर है, उस समय 2 अक्तूबर, 2019 तक सभी जगह सफाई के साथ स्वच्छ भारत की प्रधानमंत्री की अपील एक ऐसा विचार है, जिसका समय आ चुका है।

खुले में शौच मानव सभ्यता के आरंभ से ही जारी है। भारत में सदियों तक यह लाखों लोगों की जीवनशैली का हिस्सा रहा है। एक के बाद एक सरकारें 1980 के दशक से ही राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम चलाती आ रही हैं, लेकिन 2014 तक केवल 39 प्रतिशत लोगों को सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं हासिल हो सकी थीं। इसका कारण यह है कि स्वच्छता तक पहुंच बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्या नहीं है बल्कि इसमें अधिक गहरा व्यवहार संबंधी एवं सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ काम करता है। 60 करोड़ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ऐसी चुनौती है, जिसका बीड़ा संभवतः दुनिया में कभी किसी ने नहीं उठाया है। इसे सघन, समयबद्ध हस्तक्षेप से ही हासिल किया जा सकता है, जिसे सर्वोच्च स्तर से चलाया जाए और जिसमें समाज के सभी वर्ग और सरकार शामिल हों। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रह ने राष्ट्र को बिल्कुल उसी तरह प्रभावित किया है, जैसा कई वर्ष पहले महात्मा के सत्याग्रह ने किया था!

स्वच्छता का महत्व तो प्रमाणित है क्योंकि अतिसार जैसे रोगों से होने वाली शिशु मृत्यु और महिलाओं की सुरक्षा तथा गरिमा

पर इसके प्रभाव सर्वविदित हैं। किंतु स्वच्छता की कमी की जो कीमत हमें नजर आती है, उससे कहीं बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। विश्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि स्वच्छता नहीं होने के कारण ही भारत के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से कम विकसित हैं। हमारी भावी श्रमशक्ति के इतने बड़े हिस्से का अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाना हमारी सबसे बड़ी ताकत– हमारे जनांकिक लाभांश– के लिए गंभीर खतरा है। इस समस्या का समाधान ही हमारे विकास संबंधी एजेंडा के केंद्र में है और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की हमारी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक का यह अनुमान भी है कि स्वच्छता की कमी के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6 प्रतिशत से भी अधिक का नुकसान होता है।

स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव पर यूनिसेफ के हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि खुले में शौच से मुक्त गांव में प्रत्येक परिवार चिकित्सा के खर्च, समय और जीवन की रक्षा के लिहाज से हर वर्ष 50,000 रुपये बचा लेता है। इसके अलावा अच्छे ठोस तथा तरल संसाधन प्रबंधन के जरिए कचरे से संपत्ति तैयार करने की अकूत संभावना भी है। अध्ययन में निष्कर्ष दिया गया है कि 10 वर्षों में स्वच्छता से हरेक परिवार को उस पर हुए कुल निवेश (सरकारी व्यय और घरेलू योगदान समेत खर्च के अन्य साधन) से 4.7 गुना आर्थिक लाभ हो जाते हैं। इससे स्वच्छता की सुविधाएं बढ़ाने में निवेश की दलील को स्पष्ट रूप से काफी बल मिलता है।

स्वच्छ भारत मिशन के पास केंद्र तथा राज्य सरकारों से पांच वर्ष में 20 अरब डॉलर से अधिक का बजट है। निजी क्षेत्र, विकास एजेंसियों, धर्म या आस्था से संबंधित संस्थाओं एवं नागरिकों से अतिरिक्त निवेश भी आ रहा है। स्वच्छ भारत कोष में पहले ही कुछ विशेष स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 660 करोड़ रुपये एकत्र एवं जारी किए जा चुके हैं। यह धनराशि व्यक्तियों, कंपनियों एवं संस्थानों के निजी योगदान के जरिए इकट्ठी की गई है और सबसे अधिक 100 करोड़ रुपये का योगदान धर्मगुरु माता अमृतानंदमयी से मिला है!

ढेरों निजी कंपनियों ने अपने सीएसआर कोष से विशेष रूप से स्कूलों में स्वच्छता के लिए काम किया है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के लिए निजी क्षेत्र की रचनात्मकता तथा नवाचार का फायदा उठाने की अभी बहुत संभावना बाकी है। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपने–अपने क्षेत्रों में स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने सफाई तथा स्वच्छता के लिए अलग से बजट भी रखा है, जो वित्त वर्ष 2017–18 के लिए कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

स्वच्छ भारत मिशन तेजी से जनांदोलन बनता जा रहा है। भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या घटाकर 30 करोड़ के करीब लाने में यह पहले ही सफल हो चुका है और अब 68 प्रतिशत से भी अधिक भारतीयों को स्वच्छता के सुरक्षित साधन उपलब्ध हैं। लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। इसकी रफ्तार और बढ़ाने के लिए सरकार ने 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2017 के बीच स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आरंभ किया है। इस पखवाड़े के दौरान समाज के सभी वर्ग – मंत्रालय, सांसद, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, चर्चित हस्तियां, संगठन, कंपनियां, स्थानीय नेता एवं नागरिक – श्रमदान कर स्वयं को स्वच्छता के प्रति समर्पित करेंगे और इस तरह स्वच्छ भारत मिशन की ऊर्जा दूर–दूर तक फैल जाएगी।

समय आ गया है कि सभी कमर कस लें और स्वच्छ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, ऐसे भारत के निर्माण में, जिसका सपना महात्मा ने देखा था। यदि आप यह पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़े और अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं।

(लेखक केंद्रीय वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्री हैं।)
ईमेल : office@arunjaitley.com